

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन/निगरानी/भिण्ड/भूरा./2017/2507 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 17-7-2017 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड - प्रकरण
क्रमांक 46/2016-17 निगरानी

1- रबिन्द्र कुमार 2- रमाकान्त
पुत्रगण कृपाराम ग्राम कनावर मजरा भगत
की गढ़िया तहसील व जिला भिण्ड
विरुद्ध

—आवेदकगण

ठाकुर कनक विहारी राम आश्रम
विजयराघव कुँज केदार बन वृन्दावन
द्वारा महन्त रामभूषण दास उर्फ राधेश्याम
गुरु विजयराम निवासी ग्राम खनेता
तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 6 - 03 - 2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 46/2016-17 अपील
में पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अनावेदक ने आवेदकगण के विरुद्ध ठाकुर कनक
विहारी राम आश्रम विजयराघव कुँज केदार बन वृन्दावन के नाम की ग्राम कनावर मजरा भगत
की गढ़िया तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 1.702 हैक्टर (आगे

जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर जबरन कब्जा करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार भिण्ड के यहाँ दावा प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 01/2016-17 अ-70 पेंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7-7-17 पारित किया एवं वादग्रस्त भूमि पर से आवेदकगण को बेदखल करने के आदेश के साथ अवैध कब्जा करने के कारण भूमि के बाजार मूल्य का 20 % रू. 4,42,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के यहाँ अपील मेमो के साथ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत होने के उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-2017 से प्रकरण पेंजीबद्ध करने एवं रिस्पाण्डेन्ट के साथ रिकार्ड तलबी के आदेश दिये एवं धारा-52 के आवेदन पर विचार हेतु प्रकरण में आगामी तिथि 11-8-17 नियत की। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-17 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।


4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने एक ओर अपील को दर्ज किये जाने का आदेश दिया है और दूसरी ओर बिना कोई बताये स्थगन आवेदन पत्र विचार हेतु नियत किया है जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आवेदन को अप्रत्यक्ष रूप से लम्बित रखने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। प्रारंभिक न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप आवेदकगण को कब्जे से बंचित होने की संभावना एवं अपूर्तनीय हानि होने की संभावना के कारण स्थगन आवेदन पर विचार करना चाहिये था। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17-7-2017 को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि मंदिर की है एवं निशःक्त मूर्ति भूमिस्वामी

भूमिस्वामी है जिसकी भूमि पर आवेदकगण जबरन कब्जा किये है । अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दि. 17-7-17 में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण दर्ज करके धारा 52 के आवेदन पर निर्णय के पूर्व अनावेदकगण को तलब करने,रिकार्ड मंगाने के आदेश दिये है जिससे प्रकरण की पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके । इस अंतरिम आदेश से आवेदकगण को किसी प्रकार की हानि नहीं है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17-7-17 को अपील प्रस्तुत होने के उपरांत प्रकरण दर्ज करने एवं रिस्पा0 को तलब करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड देखकर धारा-52 के आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रकरण में आगामी पेशी 11-8-17 को नियत की है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण लम्बित रखने एवं मंदिर पेटे की निशःक्त मूर्ति भूमिस्वामी की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रखने के उद्देश्य से यह निगरानी की है क्योंकि आगामी पेशी 11-8-17 पर अनुविभागीय अधिकारी के के समक्ष आवेदकगण को धारा 52 के आवेदन पर सुनवाई करने का अवसर प्राप्त था , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के अंतरिम आदेश दिनांक 17-7-17 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है ऐसी स्थिति में निगरानी में विधिक वल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के प्रकरण कमांक 46/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।


(एस0एस0अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर